

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2018—आश्विन 13, शक 1940

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री गोविन्दराम चुरेन्द्र, भा.प्र.से. (2003), संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास तथा अतिरिक्त प्रभार वक्फ सर्वे आयुक्त एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री पदुम सिंह एल्मा, भा.प्र.से. (2010), अपर आयुक्त, श्रम तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग तथा वक्फ सर्वे आयुक्त एवं प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नया रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री ईमिल लकड़ा, भा.प्र.से. (2003), विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा विशेष सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करता है।

2. श्री कार्तिकेय गोयल (2010), महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, संस्थागत वित्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

3. श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), उप सचिव, वाणिज्यिक कर (आब.) विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, पंचायत के पद पर पदस्थ करते हुए उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

4. श्री तारन प्रकाश सिन्हा, भा.प्र.से. (2012), संचालक, पंचायत तथा अतिरिक्त प्रभार उप सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, वाणिज्यिक कर (आब.) विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2018

क्रमांक ई 7-07/2007/एक-2.—श्री एन. के. खाखा, सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को दिनांक 02-07-2018 से दिनांक 04-08-2018 तक स्वीकृत लघुकृत अवकाश की निरंतरता में दिनांक 05-08-2018 से दिनांक 10-08-2018 तक लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही दिनांक 11 एवं 12 अगस्त, 2018 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री खाखा आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।

3. अवकाश काल में श्री खाखा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खाखा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

**गृह (पुलिस) विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

रायपुर, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्रमांक/एफ 7/13/2015/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री मुकेश गुप्ता, (भापुसे-1988), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू/एसीबी., छत्तीसगढ़ को दिनांक 13 अगस्त 2018 से दिनांक 25 अगस्त 2018 (कुल 13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही दिनांक 11, 12 एवं 26 अगस्त 2018 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता, आगामी आदेश तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू/एसीबी, छत्तीसगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश काल में श्री गुप्ता को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है यदि श्री मुकेश गुप्ता (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**डी. पी. कौशल**, अवर सचिव.

**वन विभाग**  
**मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर**

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 1-02/2018/10-भा.व.से.—राज्य शासन, एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पदस्थापना पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री राजेश गोवर्धन, भा.व.से. (1986).	प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर (प्रभारी).	अपर प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर
2.	श्री आर.बी.पी. सिन्हा, भा.व.से. (1986).	अपर प्रधान मुख्य, वन संरक्षक, एस.ई.सी.एल., बिलासपुर, मुख्यालय रायपुर (प्रतिनियुक्ति पर).	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.
3.	श्री जे.ए.सी.एस. राव, भा.व.से. (1987).	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.
4.	श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, भा.व.से. (1987).	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री व्ही. श्रीनिवास राव, भा.प्र.से. (1990).	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.

श्री व्ही. श्रीनिवास राव, भा.व.से. (1990) के मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर के प्रभार से मुक्त होने पर मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) कांकेर वृत्त, कांकेर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 1-03/2018/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा श्री कृष्ण चंद्र यादव, भा.व.से. (1984) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान अनुसूची-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 16 (रु. 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नत करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

2. श्री कौशलेन्द्र सिंह, भा.व.से. (1985) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद एवं वेतनमान अनुसूची-III के वेतन मेट्रिक्स के लेबल 16 (रु. 2,05,400-2,24,400) में पदोन्नत करते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है.

3. श्री कृष्ण चंद्र यादव, भा.व.से. (1984) के प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लि., रायपुर का प्रभार ग्रहण करने पर श्री पी. सी. पाण्डेय, भा.व.से. (1987) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (मा.सं.वि./सू.प्रौ.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

4. श्री कौशलेन्द्र सिंह, भा.व.से. (1985) के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण-सह-मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर का प्रभार ग्रहण करने पर श्री जय सिंह महस्के, भा.व.से. (1988) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.राज./सम.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ नया रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा./अराज.) कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नया रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 1-08/2014/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा श्री राकेश चतुर्वेदी, भा.व.से. (1985) मुख्य वन संरक्षक को दिनांक 18-02-2014 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर वेतनबैण्ड HAG : 67000 (वार्षिक वेतन वृद्धि 3%) - 79000 तथा ग्रेड वेतन शून्य में पदोन्नति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. के. टोप्पो, विशेष सचिव.

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 अगस्त 2018

क्रमांक 7173/4332/2017/18.— श्री अभिनव अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर को दिनांक 03-10-2018 से 18-10-2018 (16 दिवस) तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नया रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे।
3. अवकाश अवधि में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे।
4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 7-19/2015/32.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, आयुक्त सह संचालक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत अहिवारा विकास योजना 2031 का अनुमोदन करती है। अहिवारा विकास योजना, 2031 उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जा रही है।

2. अहिवारा विकास योजना 2031 की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी :—
  1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग (छ.ग.)
  2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग (छ.ग.)
  3. कलेक्टर, दुर्ग (छ.ग.)
3. छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राजपत्र में उक्त सूचना के प्रकाशन के दिनांक से अहिवारा विकास योजना 2031 प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2018

क्रमांक एफ 7-19/2015/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में अहिवाड़ा विकास योजना 2031 इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 21-8-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

Naya Raipur, the 21st August 2018

No. F 7-19/2016/32.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 the State Government hereby accord approval to the Ahiwara Development Plan 2031 submitted by Commissioner cum Directorate under sub section (3) of section 18 of said Adhiniyam. Ahiwara Development Plan 2031 is being published in “Chhattisgarh Rajpatra” for as required by sub-section (4) of section 19 of the said Adhiniyam.

2. The copy of the approved Ahiwara Development Plan 2031 shall be available during office hours for inspection in the following offices :—

1. Joint Director, Town & Country Planning, Regional Officer Durg (C.G.)
2. Commissioner, Municipal Corporation, Durg (C.G.)
3. Collector, Durg (C.G.)

3. The Ahiwara Development Plan 2031 shall come into operation from the date of publication of the said notice in Chhattisgarh Rajpatra as per the provision of sub-section (5) of section 19 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order in the name of Governor of Chhattisgarh,  
REGINA TOPPO, Addl. Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितंबर 2018

क्रमांक 3159/5048/2017/11/(6).—राज्य शासन एतद्वारा इस विभाग की समसंख्यक आदेश दिनांक 13-08-2018 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित उद्योगों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट के नियमानुसार डिस्पोजल किये जाने हेतु कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी व्यवस्था हेतु गठित समिति के बिन्दु क्र-3 उद्योग संघ के तीन प्रतिनिधि-सदस्य में निम्नानुसार प्रतिनिधि नामांकित करता है :—

1. श्री मनोज कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, छ.ग. स्टील रि-रोलर्स एसोसिएशन
2. श्री उमेश चितलंगिया, प्रतिनिधि, लघु उद्योग भारती
3. श्री पी. एस. दत्तागुप्ता, प्रतिनिधि, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज

2. उक्त नामांकन कार्यविशेष के संपन्न होने की अवधि तक प्रभावशील रहेंगे. शासन को नामांकन/अवधि में परिवर्तन का अधिकार होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 5 सितम्बर 2018

क्रमांक 55/9 अ-82/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	दाऊगुड़ी	1.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	दाऊगुड़ी व्यपवर्तन योजना के दांयी एवं बांयी नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 5 सितम्बर 2018

क्रमांक 56/8 अ-82/भू-अर्जन/2018.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुंद	सरायपाली	कनपला	1.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	कनपला व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

जगदलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	नगरनार प.ह.नं. 13	9.60	अधिशाली निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट नगरनार, जिला बस्तर.	एन.एम.डी.सी., आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर/अधिशाली निदेशक, एन.एम.डी.सी. आयरन एंड स्टील प्लांट, नगरनार, के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.**

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बहिरकेला	0.129	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	ग्राम बहिरकेला के राजातालाब जलाशय योजना हेतु अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.



रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 26/अ-82/2017-18.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बरौद	0.283	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बरौद एनीकट के डूब क्षेत्र में प्रभावित भू-खण्ड अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2017-18.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बुलेकेरा प.ह.नं. 09	0.077	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन धरमजयगढ़.	बुलेकेरा एनीकट के डूब क्षेत्र हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 35/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बैहामुड़ा	6.376	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बैहामुड़ा बैराज निर्माण हेतु अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बुलेकेरा	2.416	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बुलेकेरा एनीकट के डूब क्षेत्र में प्रभावित भू-खण्ड का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 सितम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	बडेगुमडा	5.756	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	बैहामुड़ा बैराज निर्माण हेतु ग्राम बडेगुमडा की प्रभावित भू-खण्ड का

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 22 जून 2018

क्रमांक/10637/भू-अर्जन/44 अ 82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कोरबा प.ह.नं. 09	0.66	आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा.	सर्वमंगला बाईपास सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्रमांक/13714/भू-अर्जन/14 अ 82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोरबा  
(ख) तहसील-कोरबा  
(ग) नगर/ग्राम-करमंदी  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.497 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
39/1	0.028
37/1	0.130
39/2	0.028
37/2	0.130
39/3	0.028
37/3	0.130
49/6	0.008
36/2, 38/1	0.202
37/4	0.130
49/7	0.008
95/3	0.202
101/4	0.162
102/2	0.089
103	0.040
104	0.105
49/5	0.012
108	0.065
योग	17
	1.497

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करमंदी एनीकट योजना के बांध लाईन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 27 अगस्त 2018

क्रमांक/14150/भू-अर्जन/11 अ 82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-कोरबा  
(ख) तहसील-कोरबा  
(ग) नगर/ग्राम-चीतापाली  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
212/1, 228/3	0.093
228/2	0.028
214/3	0.008
240/4, 307/1, 309, 310/2	0.040
310/5	0.065
योग	5
	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चीतापाली एनीकट योजना के बांध लाईन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मो. कैसर अब्दुल हक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा,  
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्रमांक/13815/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा  
(ख) तहसील-सक्ती  
(ग) नगर/ग्राम-असौंदा, प.ह.नं. 14  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
550/1	0.012
808	0.016
810	0.040
योग	03 0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अचानकपुर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्रमांक/13817/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा  
(ख) तहसील-जैजैपुर  
(ग) नगर/ग्राम-ठठारी, प.ह.नं. 02  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2163	0.405
योग	01 0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सोनसरी एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्रमांक/13819/अ-82/2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-जांजगीर-चांपा  
(ख) तहसील-जैजैपुर  
(ग) नगर/ग्राम-कचंदा, प.ह.नं. 12  
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
468	0.008

	(1)	(2)
	473/1	0.028
योग	02	0.036
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचंदा उपवितरक नहर निर्माण हेतु.		
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.		
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार बनसोड़, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.		
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग		

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बेहराचुंआ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.719 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.052
9/3	0.020
16/6	0.008
9/1	0.016
15/1	0.080
6	0.020

(1)	(2)
16/2	0.024
56/1	0.016
24/1	0.024
16/4ग	0.012
15/2	0.020
7	0.020
19	0.020
62	0.052
24/2	0.016
16/4 क	0.016
14/1	0.020
2/1क	0.028
10/1	0.045
20	0.045
24/3	0.045
2/1ख	0.028
14/2	0.020
56/3	0.072

योग 24 0.719

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

#### अनुसूची

##### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अमझर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.260 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.020
11/1	0.048
10/2क	0.024
36	0.020
10/2ख	0.024
11/2	0.020
10/3घ	0.028
10/2घ	0.076
योग	8

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धौराभांठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.614 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
116/2	0.012
117/5	0.036
117/2ख	0.024
117/4ख	0.020

(1)	(2)
133	0.040
116/3	0.008
117/7	0.040
117/6ख	0.020
117/8ख	0.028
114	0.182
117/1	0.024
117/2क	0.024
117/4क	0.020
117/4ग	0.020
117/3	0.048
117/6क	0.020
117/8क	0.024
117/8ग	0.024
योग	18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गुडेली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
551/1ख	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
602/2क	0.024	493	0.072
599/3ग	0.004	510/1	0.314
599/3क	0.004	511/2	0.052
598	0.008	505/4	0.024
599/6	0.008	505/2	0.008
599/3ख	0.004	511/9	0.017
599/1	0.012	507/6	0.060
599/7	0.008	570/3	0.004
599/5	0.008	568/2	0.008
599/2	0.012	500/2	0.020
योग	11	577/2	0.004
		495/1	0.012
		516/3	0.012
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु,		496/2	0.012
		566	0.012
		563	0.024
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.		509	0.068
		511/1	0.040
		511/8	0.017
		507/1	0.040
रायगढ़, दिनांक 31 अगस्त 2018		507/13	0.020
		570/2	0.004
भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		504/2च, 505/3	0.008
		508	0.060
		569/3	0.004
		576/1	0.016
		569/2	0.004
		495/2	0.012
		567	0.024
		562	0.008
		499/1	0.032
		511/3	0.028
		505/1	0.008
		507/7	0.036
		571	0.012
(1) भूमि का वर्णन-		570/1	0.004
(क) जिला-रायगढ़		511/14	0.008
(ख) तहसील-सारंगढ़		511/7	0.017
(ग) नगर/ग्राम-लालाधुरवा		516/1	0.014
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.443 हेक्टेयर		577/1	0.004
खसरा नम्बर	रकबा	516/2	0.008
	(हेक्टेयर में)	568/3	0.008
(1)	(2)	561/2	0.008
		515	0.040
576/2	0.016	498/2	0.016
496/1	0.012	511/5	0.008
569/1	0.004	511/6	0.008
513	0.020	507/3	0.048



(1)	(2)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.
507/11	0.044	
568/1	0.008	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.
494	0.032	
578	0.020	
योग	56	1.443

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास

छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला-रायपुर

क्रमांक शा-1/विविध/4835/2018/14004

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2018

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उप-धारा (1) सहपठित धारा 133 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में जारी तत्प्रतिकूल समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, नगरपालिक निगम, एतद्वारा, जनहित में अपने क्षेत्राधिकार के भीतर समस्त शहरी क्षेत्रों में बाजार शुल्क की वसूली 1 अप्रैल, 2018 से समाप्त करती है.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 132 read with sub-section (1) of Section 133 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in supersession of all orders to the contrary issued in this regard and in compliance of the directions of the State Government, the Municipal Corporation, hereby, abolishes levy of Market Fee in all urban areas within its jurisdiction with effect from 1st day of April 2018 in public interest.

हस्ता./-

आयुक्त.

क्रमांक शा-1/विविध/4835/2018/14004

अटल नगर, दिनांक 7 सितम्बर 2018

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127 की उपधारा (1) सहपठित धारा 129 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में जारी तत्प्रतिकूल समस्त आदेशों को अधिक्रमित करते हुए तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुपालन में, नगरपालिका, एतद्वारा, जनहित में अपने क्षेत्राधिकार के भीतर समस्त शहरी क्षेत्रों में बाजार शुल्क की वसूली 1 अप्रैल, 2018 से समाप्त करती है.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 127 read with sub-section (1) of Section 129 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in supersession of all orders to the contrary issued in this regard and in compliance of the directions of the State Government, the Municipality, hereby, abolishes levy of Market Fee in all urban areas within its jurisdiction with effect from 1st day of April, 2018 in public interest.

हस्ता./-

मुख्य नगरपालिका अधिकारी.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 सितम्बर 2018

CEERTIFICATE OF TRANSFER OF CHARGE

क्र. 1844/पंग्रावि/2018.—Certified that we have in the force/afternoon of this day respectively made over and received charge of the office of Deputy Secretary, Commercial Tax (Excise) & Director, Culture & Archeology in pusuance of order No. ई-1-1-2018/1/2 dated 04-09-2018 and that the officer receiving charge travelled during joining time on 05-09-2018 (mentioned dates).

हस्ता./-  
अवर सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 31st August 2018

No. 886/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Shailesh Sharma, II Civil Judge Class-I.	Raipur	Mungeli	Mungeli	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate.

**Note :—** The above officer is entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 only after appraisal of the work and performance by the High Court.

Bilaspur, the 31st August 2018

No. 888/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No.

(6) from the date she assumes charge of her office:—

TABLE

Sl. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Shivani Singh, I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Gharghora	Raigarh	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raigarh at Gharghora

Bilaspur, the 31st August 2018

No. 890/Confdl./2018/II-3-1/2018.—The following candidates as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government are posted in the capacity as mentioned against their names in Column No. (3) of the table below with a direction to join their place of posting on or before 14-09-2018 :—

TABLE

Sl. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Akanksha Saxena, D/o Late Shri Anil Kumar Saxena.	XV Civil Judge Class-II, Durg
2.	Shri Rahul Kumar, S/o Shri Mukesh Kumar Sharma	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Dhamtari.
3.	Ku. Ruchi Mishra, D/o Shri Santosh Kumar Mishra	XVI Civil Judge Class-II, Durg
4.	Shri Himanshu Arya, S/o Shri Sahdev Arya	VII Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Raipur.
5.	Shri Parth Tiwari, S/o Shri S. C. Tiwari	Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Balod.
6.	Shri Nikhil Kumar Sushmakar, S/o Late Shri Raman Lal Sushmakar.	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Bilaspur.

बिलासपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2018

क्रमांक 373/दो-2-7/2013.—श्री सतीश कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, दुर्ग दिनांक 31-07-2018 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,  
नीलम चंद सांखला, रजिस्ट्रार जनरल.

---

Bilaspur, the 27th July 2018

No. 7123/Checker/III-6-2/2007.—In exercise of the powers conferred under clause (c) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers (i) Shri Pankaj Dixit, Judicial Magistrate First Class, Pithora, & (ii) Shyam Kumar Sahu, Judicial Magistrate, First Class-Basna, District-Mahasamund to try in a summary may all or any of the offences specified in the said Section.

By order of Hon'ble the High Court,  
Sd/-  
I/c Registrar General.

---